साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार 12 -18 सितंबर 2022, वर्ष-8, अंक-23
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

अब गैर बासमती चावल पर अब लगेगा 20 फीसदी निर्यात शुल्क

मप्र सहित 15 राज्यों में घटा 22 लाख हेक्टेयर धान का रकबा

» देश में मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों व सरकारों की चिंता

» इस साल अब तक 129.55 लाख हेक्टेयर में दलहन की बोवनी हुई

» खरीफ सीजन में दो सितंबर तक रकबा 188.51 लाख हेक्टेयर रहा

» नकदी फसलों में, कपास का रकबा 125.69 लाख हेक्टेयर रहा

» अब तक जूट व मेस्टा का रकबा 6.95 लाख हेक्टेयर दर्ज किया

भोपाल। अरविंद मिश्र

साल-2022 में देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश से धान के रकबे में मामूली ही सही, बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में बारिश की कमी ने धान का 22 लाख हेक्टेयर रकबा घट गया है। वहीं केंद्र सरकार ने उसना चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगा दिया है। चालू खरीफ सत्र में धान फसल का रकबा काफी घट गया है। ऐसे में घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून की बेरुखी घातक साबित होने वाली है। इसका असर मौसम के उतार-चढ़ाव में दिखने लगा है। देश के कई राज्य बाढ़ से घिरे हैं। वहीं कई जगह सूखे की धमक सुनाई देने लगी है। इन सबके बीच देश का खरीफ सीजन का कृषि-चक्र प्रभावित हुआ है। खरीफ फसलों की बोवनी कम होना, चिंता की बात है। राज्यों के साथ केंद्र सरकार भी चिंतित है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़े इसके प्रमाण हैं। आंकड़ों के मुताबिक मप्र सहित 15 राज्यों में कम बारिश ने धान का रकबा घटा दिया है। वहीं, 12 राज्य ऐसे भी हैं, जहां बोवनी ठीक-ठाक हुई है। चालू खरीफ सीजन में अब तक धान की फसल का रकबा 5.62 प्रतिशत घट गया है। सरल भाषा में कहें तो इस साल देश में धान की खेती कम हुई है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 21 लाख हेक्टेयर में कम बारिश के कारण धान की बोवनी नहीं हो पाई।

छह राज्यों में मामूली कमी

इस साल खरीफ सीजन में धान का रकबा 383.99 लाख हेक्टेयर रहा है। एक साल पहले इसी अवधि में धान की बोवनी 406.89 लाख हेक्टेयर में की गई थी। धान मुख्य खरीफ फसल है। इसकी बोवनी जून से दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ होती है। देश के कई राज्यों में धान का रकबा कम हुआ है। आधा दर्जन राज्यों में ज्यादा तो कई अन्य में मामूली कमी आई है।

मप्र में 6.32 लाख हेक्टेयर कमी

बिहार-झारखंड, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कम बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। बिहार में 2.18 लाख हेक्टेयर तो झारखंड में 9.80 लाख हेक्टेयर का रकबा कम हुआ। मध्यप्रदेश में यह 6.32 लाख हेक्टेयर है तो छत्तीसगढ़ में 3.91 लाख हेक्टेयर है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2.61 लाख हेक्टेयर रकबा घटा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 4.45 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय ने कई अन्य राज्यों में भी धान का रकबा घटने का जिक्र किया है।

12 राज्यों में अच्छी बोवनी

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, पंजाब, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर में धान की बोवनी में कमी आई है। पिछले साल इन राज्यों में जहां 135.46 लाख हेक्टेयर में धान की बोवनी हुई थी। इस साल वह घटकर 129.55 लाख हेक्टेयर रह गई है। देश के 15 राज्यों में इस खरीफ सीजन में जहां धान का रकबा कम हुआ है। वहीं 12 राज्य ऐसे भी हैं, जहां बोवनी अच्छी हुई है। तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में धान की अच्छी फसल होने की संभावना है।

दलहन फसलों में गिरावट

इस साल अब तक 129.55 लाख हेक्टेयर में दलहन की बोवनी हुई है। एक साल पहले यह 135.46 लाख हेक्टेयर थी। अरहर का रकबा 47.56 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 44.86 लाख हेक्टेयर रहा है। उड़द का रकबा पिछले साल 38.18 लाख हेक्टेयर था, जो इस सीजन में 36.62 लाख हेक्टेयर रहा है। तिलहन फसलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

14 राज्यों में कम बारिश का असर

कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस खरीफ सीजन में 2 सितंबर तक रकबा 188.51 लाख हेक्टेयर रहा है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 189.66 लाख हेक्टेयर था। दलहनी फसलों के रकबे में कमी पर गौर करें तो इस खरीफ सीजन में अब तक 14 राज्यों में कम बारिश का असर पड़ा है। इनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं।

नगदी फसलों की बढ़ी पैदावार

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नकदी फसलों में, कपास का रकबा 125.69 लाख हेक्टेयर रहा। वहीं गन्ने का रकबा एक साल पहले की अवधि की तुलना में 55.65 लाख हेक्टेयर से थोड़ा अधिक था। आंकड़ों से पता चलता है कि चालू खरीफ सीजन में अब तक जूट/मेस्टा का रकबा 6.95 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया।

सूखे की चपेट में विंध्य

मध्यप्रदेश का वहीं विंध्य अंचल सूखे से जूझ रहा है। चंबल, मालवा, महाकौशल पानी से तरबतर हो चुके हैं, लेकिन विंध्य क्षेत्र भीषण सूखे की चपेट में पहुंच गया है। आषाढ़ में बूंदाबादी हुई, सावन में धूल उड़ी और भादौ पूरी तरह से सूखा निकला। मौसम विभाग के सभी पूर्वानुमान विंध्य में फेल हो गए। किसान बेबस और परेशान नजर आ रहे हैं। खेत खाली पड़े हैं। रोपा की धान तैयार होकर सूख रही है।

यहां घटा रकबा

राज्य	क्षेत्रफल
झारखंड	9.80 लाख हेक्टेयर
मध्यप्रदेश	6.32 लाख हेक्टेयर
प. बंगाल	4.45 लाख हेक्टेयर
छत्तीसगढ़	3.91 लाख हेक्टेयर
उत्तर प्रदेश	2.61 लाख हेक्टेयर
बिहार	2.18 लाख हेक्टेयर

यहां कम हुई धान की बोवनी

राज्य	क्षेत्रफल
ओडिशा	0.84 लाख हेक्टेयर
आंध्रप्रदेश	0.31 लाख हेक्टेयर
असम	0.29 लाख हेक्टेयर
मेघालय	0.21 लाख हेक्टेयर
पंजाब	0.12 लाख हेक्टेयर
जम्मू-कश्मीर	0.05 लाख हेक्टेयर
मिजोरम	0.03 लाख हेक्टेयर
सिक्किम	0.02 लाख हेक्टेयर
त्रिपुरा	0.01 लाख हेक्टेयर

यहां बढ़ा धान का रकबा

राज्य	क्षेत्रफल
तेलंगाना	4.71 लाख हेक्टेयर
हरियाणा	0.94 लाख हेक्टेयर
नागालैंड	0.78 लाख हेक्टेयर
गुजरात	0.55 लाख हेक्टेयर
राजस्थान	0.34 लाख हेक्टेयर
महाराष्ट्र	0.30 लाख हेक्टेयर
हिमाचल	0.14 लाख हेक्टेयर
कर्नाटक	0.09 लाख हेक्टेयर
तमिलनाडु	0.08 लाख हेक्टेयर
अरुणाचल	0.08 लाख हेक्टेयर
केरल	0.04 लाख हेक्टेयर
उत्तराखंड	0.03 लाख हेक्टेयर

यहां ज्याद हुई बोवनी

राज्य	क्षेत्रफल
मध्यप्रदेश	4.08 लाख हेक्टेयर
उत्तर प्रदेश	0.22 लाख हेक्टेयर
असम	0.11 लाख हेक्टेयर
तमिलनाडु	0.08 लाख हेक्टेयर
जम्मू कश्मीर	0.06 लाख हेक्टेयर
नागालैंड	0.02 लाख हेक्टेयर

यहां पैदावार होगी कम

राज्य	क्षेत्रफल
महाराष्ट्र	3.23 लाख हेक्टेयर
तेलंगाना	1.70 लाख हेक्टेयर
झारखंड	1.33 लाख हेक्टेयर
कर्नाटक	0.09 लाख हेक्टयर
गुजरात	0.88 लाख हेक्टेयर
आंध्र प्रदेश	0.77 लाख हेक्टेयर
राजस्थान	0.67 लाख हेक्टेयर
हरियाणा	0.38 लाख हेक्टेयर
उत्तराखंड	0.17 लाख हेक्टेयर
ओडिशा	0.13 लाख हेक्टेयर
छत्तीसगढ़	0.12 लाख हेक्टेयर
बिहार	0.10 लाख हेक्टेयर
पश्चिम बंगाल	0.03 लाख हेक्टेयर

ईओडब्ल्यू ने की थी 25 समितियों की जांच, तीन में मिला 27 लाख से अधिक का घोटाला

धान खरीदी में घपला, तीन समितियों पर एफआईआर

प्रवीन नामदेव। जागत गांव हमार

जबलपुर। धान खरीदी में कुसनेर, गोसलपुर और बनखेड़ी की धान खरीदी समितियों में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, जिसकी जांच करते हुए ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। तीनों समितियों ने वर्ष 2003-2004 में भ्रष्टाचार करते हुए करीब 27 लाख से अधिक रुपए का घोटाला किया था। जांच में पाया गया है कि मानक पैदावार से धान की अधिक पैदावार बताकर सहकारी समितियों में धान का विक्रय कागजों में कराकर अवैध लाभ अर्जित किया गया है। इसमें गोसलपुर, कुशनेर और बनखेड़ी के तत्कालीन समिति प्रबंधक, अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध लाभ अर्जित किया है। इन तीनों प्रकरणों में एक भोलाराम नामक कृषक व अन्य शामिल हैं।

गोसलपुर समिति में भ्रष्टाचार

गोसलपुर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर, कृषक रामकुमार, भोलाराम एवं अन्य ने धान खरीदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया। शासन को छह लाख, 35 हजार 249 की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। जिसमें सभी आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

कुशनेर समिति में भ्रष्टाचार

कुशनेर समिति की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमति शशिबाई पटेल, प्रबंधक हरिशंकर दुबे, कृषक बैजनाथ, भोलाराम एवं अन्य ने धान खरीदी में भ्रष्टाचार किया है। सभी ने मिलकर 13 लाख, 84 हजार, 830 रुपए की आर्थिक क्षति शासन को पहुंचाई है।

इन 25 समितियों की हुई थी शिकायत-

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शहपुरा मार्केटिंग पनवानी, नुनियाकला, गोसलपुर, मझगवां, मंझौली, शहपुरा, कुशनेर, सकरारोझा, पाटन खेड़ी, कापा बनखेड़ी, नगना, पनागर, सिहोरा, औरिया, सहजपुर, बोरिया, घनसुर, बरेला, कटंगी और नुनसर सहित कुल 25 समितियों में इस भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। ईओडब्ल्यू निरीक्षक शशिकला मस्कुले ने सभी की जांच की। जिसमें तीन समितियों में गड़बड़झाला उजागर हुआ है।

बनखेड़ी समिति में भी भ्रष्टाचार

बनखेड़ी समिति में पदस्थ तत्कालीन अध्यक्ष रामसिया सिंह ठाकुर, प्रबंधक हबीब खान, कृषक बैजनाथ, भोलाराम व अन्य ने मिलकर धान खरीदी में भ्रष्टाचार किया है। जिसमें शासन को सात लाख, 50 हजार, 750 रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है।

धान खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत जांच में तीन समितियों द्वारा भ्रष्टाचार करना पाया गया है, जिसमें धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जल्द ही आगे की कार्रवाई होगी।

-देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, एसपी, ईओडब्ल्यू

बारिश में बिना खेती ही कमाई का बना जरिया

चंबल के बीहड़ का ककोड़ा बना रहा लोगों की 'सेहत'

अवधेश डंडौतिया, जागत गांव हमार

मुरैना। बारिश के मौसम में चंबल अंचल में उगने वाला ककोड़ा बिना खेती के ही हजारों लोगों की कमाई का बड़ा जरिया है। बीहड़ों में उगने वाली 100 फीसद जैविक सब्जी की खेती कोई किसान नहीं करता, इसके बावजूद कई दशकों से यह सब्जी चंबल अचंल के तीन जिलों के हजारों गरीब परिवारों, सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं के लिए कमाई का साधन बनी हुई है। औषधि गुणों और पौष्टिक तत्वों से भरा ककोड़ा सेहत के लिए फायदेमंद होने के कारण ढाई से तीन माह में इनकी मांग अधिक रहती है। मुरैना के अलावा भिंड और श्योपुर के जंगली क्षेत्र और बीहड़ किनारों की झाड़ियों व घासफूंस के बीच ककोड़ा भरपूर मात्रा में होता है। इसकी मांग ग्वालियर से लेकर आगरा, दिल्ली, जयपुर, इंदौर व अन्य कई महानगरों में है। अंचल में यह सब्जी 100 से 200 रुपये किलो तो महानगरों में 300 से 400 रुपए किलों के भाव बिकती है। बारिश के सीजन में जब रोजगार के कई रास्ते बंद होते हैं, तब ककोड़ा की सब्जी अंचल के ढाई हजार से ज्यादा परिवारों की आमदनी का इकलौता जरिया है। एक अनुमान के हिसाब से चंबल अंचल में हर साल 400 से 425 टन ककोड़ा की पैदावार होती है। शून्य खर्च में होने वाली इस सब्जी को बाजार में खपाने के लिए सब्जी मंडियों के आड़तिए, थोक व खेरीज दुकानदार और इन्हें जंगल से तोड़ने वाले गरीब व आदिवासी परिवार तीन से साढ़े तीन करोड़ रुपए कमाते हैं।

कई बीमारियों में फायदेमंद

मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. संदीप सिंह तोमर बताते हैं कि बारिश के सीजन में आने वाली हर सब्जी में कीटनाशक उपयोग होता है, लेकिन ककोड़ा पूरी तरह जैविक होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन व आयरन होता है, इसीलिए यह सेहत के लिए मीट से कई गुना ताकतवर है। 100 ग्राम ककोड़ा की सब्जी से 17 कैलोरी ऊर्जा शरीर को मिलती है, जो वजन कम करने , डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

इस साल बंपर पैदावार

अगस्त के अंत तक बाजार से गायब हो जाने वाला ककोड़ा इस साल न सिर्फ भरपूर बल्कि सस्ते दामों में भी मिल रहा है। बागवानी विशेषज्ञ एसके शर्मा बताते हैं कि ककोड़ा की बेलें सूखकर जमीन में रह जाती हैं, यह जड़ें बारिश होते ही फिर से हरियाने लगती हैं। अंचल में मई की शुरुआत में ही अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण ककोड़ा की पैदावार जल्दी और पहले से ज्यादा मात्रा में हो रही है।

ओंकारेश्वर में किसान मोर्चा की बैठक में सीएम शिवराज ने कहा

प्राकृतिक खेती करने वालों की मदद करेगी सरकार

» खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों के जीवन स्तर ऊठाएंगे

» प्राकृतिक खेती से जोड़कर जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएंगे

खंडवा। प्राकृतिक खेती से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। किसाना मोर्चा की पहल सराहनीय है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की मदद सरकार करेगी। खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तत्पर हैं। हर खेत को पानी मिले इसके लिए सरकार प्रयासरत है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ओंकारेश्वर में भाजपा किसान मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के समापन अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। भूमि सुपोषण अभियान के तहत उन्हें प्राकृतिक खेती से जोड़कर जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। मोरटक्का के पास एक होटल में आयोजित बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत, विधायक नारायण पटेल, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थिति थे। आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।

वहीं मंच पर उन्हें बैलगाड़ी का स्मृति चिह्न किसान मोर्चा की ओर से भेंट किया गया। ओंकारेश्वर में आयोजित किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सीएम ने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य के साथ किसान दर्पण पुस्तिका का विमोचन कर किसान मोर्चा के ध्येय की प्राप्ति और संकल्प सिद्धि के लिए शुभकामनाएं दी।

सीएम ने मांगे सुझाव

मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चे द्वारा दिए गए सुझाव एवं किसानों को लेकर किए जाने वाले कार्यों की बात कहते हुए सरकार द्वारा किसानों को आने वाली समस्या के निराकरण कर उसका त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चहल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को किस प्रकार की जरूरत है। और किस प्रकार किसानों के लिए बेहतर काम किया जा सकता है। इस बात को लेकर भी सीएम द्वारा सुझाव मांगे गए हैं।

जिले से 25 हजार मीट्रिक टन केला दुबई, ईरान, बहरीन सहित अन्य देशों को हो रहा एक्सपोर्ट

प्रदेश की पहली बनाना फाइबर इकाई स्थापित

बुरहानपुरी केले की बढ़ी मांग खाड़ी देशों तक पहुंची मिठास

गनेश दुनगे। जागत गांव हमार

बुरहानपुर। केला उत्पादन के लिए मशहूर मप्र के बुरहानपुर जिले की ख्याति अब खाड़ी देशों तक पहुंच चुकी है। सालाना सोलह लाख टन केले का उत्पादन करने वाले इस जिले से 25 हजार मीट्रिक टन केला दुबई, ईरान, बहरीन सहित अन्य देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। बुरहानपुरी केले की मांग बढ़ने का कारण इसकी खास क्वालिटी और जैविक खेती है। जिले में मुख्य रूप से ग्रैंड-9, बसराई, श्रीमंती और हर्षाली किस्म के केले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट ग्रेंड-9 किस्म का केला होता है। इसकी खासियत सुंदर आकार, बड़ी साइज और मिठास है। इसके अलावा इस किस्म का केला लंबे समय तक खराब नहीं होता। विदेशों में केला एक्सपोर्ट करने वाले किसानों की आय कई गुना बढ़ गइ है।

अब किसान नहीं लेते कर्ज

बुरहानपुर जिले के नाचनखेड़ा के किसान राजेश पाटिल, अमोल मावले, नीलेश चौधरी, रवींद्र पाटिल, योगेश महाजन, रामदास पाटिल आदि का कहना है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के केले के अच्छे दाम मिलने से हमार आर्थिक संपन्नता कई बढ़ गई है। अब हमें खेती के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

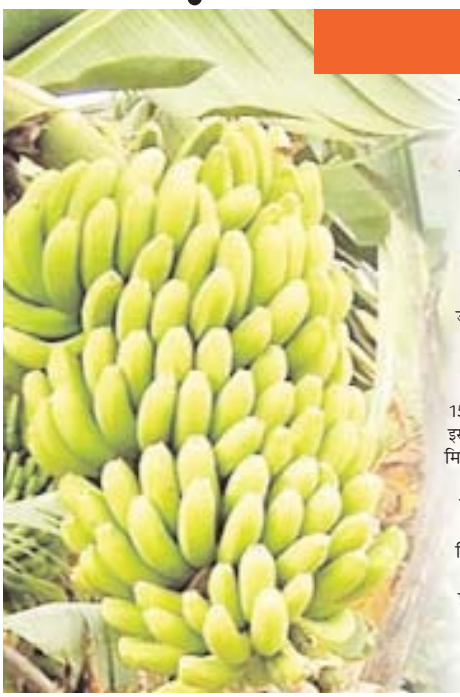

एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केले से बने उत्पाद निर्मित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खामनी निवासी किसान संदीप महाजन ने इसके तहत केला चिप्स यूनिट स्थापित की है। वे बताते हैं कि केले के पत्ते व केला चिप्स व्यवसाय से उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी ने केला चिप्स व्यवसाय बढ़ाने की जानकारी दी थी। जिससे प्रेरित होकर उन्होंने बैंक के माध्यम से 15 लाख रुपए का ऋण लिया था। इसमें 35 प्रतिशत अनुदान राशि भी मिली है। प्रतिदिन 80 से 90 किलो केला चिप्स बनाकर 150-160 रुपए प्रति किलो की दर से जिले व जिले के बाहर पुणे, चंडीगढ, दिल्ली व महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेच रहे हैं। लागत राशि काटकर प्रतिदिन शुद्ध मुनाफा तीन से चार हजार रुपए हो जाता है। अब वे सालाना आठ लाख रुपए तक कमा रहे हैं।

रोजगार के अवसर बढ़े

केले का उत्पादन बढ़ने और एक्सपोर्ट होने से जहां एक ओर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। वहीं केले के सहायक उत्पादों और प्रोसेसिंग यूनिटों से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना में भी इसे शामिल किया है। जिसके तहत केला चिप्स तैयार करने के लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग ने अब तक 40 यूनिट स्वीकृत कराई है। इनमें से 17 यूनिटों में चिप्स का उत्पादन भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी इनमें रोजाना करीब 20 क्विंटल चिप्स ही तैयार हो रहा है। इसके अलावा केले को पकाने के लिए जिले में 26 राइपनिंग चेंबर स्थापित हो चुके हैं। प्रत्येक इकाई में पंद्रह से बीस मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। केला रखने के लिए दो कोल्ड स्टोरेज और केले के रेशे से उत्पाद बनाने के लिए एक बनाना फाइबर एक्सटेंशन यूनिट भी स्थापित है।

जिले में केला उत्पादन बढ़ने के साथ ही इससे दूसरे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। केला चिप्स और केला फाइबर को लेकर तेजी से काम हो रहा है।
-आरएनएस तोमर, उप संचालक उद्यानिकी विभाग

तीन साल से बढ़ रहा उत्पादन

बीते तीन साल से जिले में केला उत्पादन बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 में 20522 हेक्टेयर में 14.36 लाख टन केला उत्पादन हुआ था। वर्ष 2021-22 में रकवा बढ़कर 22450 हेक्टेयर और उत्पादन 15.71 लाख टन हो गया। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 25 हजार हेक्टेयर में बीस हजार से ज्यादा किसानों ने केला फसल लगाई है। इस साल सकल उत्पादन 16 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है। खाड़ी देशों में 6000 मीट्रिक टन से एक्सपोर्ट की शुरुआत की गई थी जो अब 25 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गई है।

बुरहानपुर में बनाना फाइबर इकाई स्थापित

एक जिला एक उत्पाद के तहत केले से फाइबर तैयार करने वाली मप्र की पहली इकाई बुरहानपुर में स्थापित की गई है। सरकार के सहयोग से सुखपुरी मार्ग पर मंगलम कल्पतरू इंडस्ट्रीज शुरू करने वाले मेहुल श्राफ ने बताया कि इस इकाई में बनाना फाइबर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। इस रेशे से पूजा की झाड़ू, योग की मेट, आसन, घर में सजावट के लिए उपयोग होने वाले प्लांटर तैयार होते हैं। साथ ही केले के अर्क को मिलाकर हाल ही में नया उत्पाद आर्गेनिक लिक्विड न्यूट्रीएंट तैयार किया गया है। इसका उपयोग खेतों की उर्वरता बढ़ाने में किया जा रहा है। इसमें लिविंग बैक्टीरिया पाया जाता है।

देशी मुर्गी पालन से कम होती बेरोजगारी, प्रजाति एवं उनके महत्व

मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा (लाखों-करोड़ो) भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोज़गार के तौर पर अपना सकते हैं। चार दशकों में मुर्गीपालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद, कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। वर्तमान मे प्रति व्यक्ति वार्षिक 180 अण्डों की मांग के मुकाबले 86 अण्डों की उपलब्धता है (2019-20)। देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक 11 कि.ग्रा. मीट की मांग के मुकाबले केवल 3.09 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति (2019-20) कुक्कुट मीट की उपलब्धता जनसंख्या में वृद्धि जीवनचर्या में परिवर्तन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरुकता, युवा जनसंख्या के बढ़ते आकार आदि के कारण कुक्कुट उत्पादों की मांग में जबर्दस्त वृद्धि हुई है।

वर्तमान बाजार परिदृश्य में कुक्कुट उत्पाद उच्च जैविकीय मूल्य के प्राणी प्रोटीन का सबसे सस्ता उत्पाद है। मुर्गीपालन व्यवसाय से भारत में बेरोजगारी भी काफी हद तक कम हुई है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर बैंक से लोन लेकर मुर्गीपालन व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। देसी मुर्गी ब्रायलर मुर्गियों से बहुत अलग होती है। इन मुर्गियां का ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बहुत धीरे विकास होता है। फ्री रेंज चिकन को 1-2 किलो का वजन तक होने में लगभग 4-5 महीना लगता है। बहुत कम जगह में यह आराम से रह जाती हैं इसलिए इनको बड़ी आसानी से आप पाल सकते हैं।

देसी मुर्गी के कुछ मुख्य प्रजातियां: भारत मे मुर्गियों की बहुत सी प्रजातियां पायी जाती है लेकिन इन सभी प्रजातियों में से देशी मुर्गियों की प्रजाति पालन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त होती है। देसी मुर्गी निम्न प्रकार की होती है, आप इनमें से अपने अनुसार चुन सकते हैं-

भारत में मुर्गियों की नस्लें (कुक्कुट नस्ल)

1. असील नस्ल: यह नस्ल भारत के उप्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। इस नस्ल का चिकन बहुत अच्छा होता है। इन मुर्गियों का व्यवहार बहुत ही झगड़ालू होता है। मुर्गों का वजन 4-5 किलोग्राम तथा मुर्गियों का वजन 3-4 किलोग्राम होता है। इस नस्ल के मुर्गे-मुर्गियों की गर्दन और पैर लंबे होते हैं तथा बाल चमकीले होते हैं। मुर्गियों की अंडे देने की क्षमता काफी कम होती है।

2. कड़कनाथ नस्ल: इस नस्ल का मूल नाम कालामासी है, जिसका अर्थ काले मांस वाला पक्षी होता है। कड़नाथ नस्ल मूलत: मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस नस्ल के मीट में 25प्रतिशत प्रोटीन पायी जाती है जो अन्य नस्ल के मीट की अपेक्षा अधिक है। यह मुर्गिया प्रतिवर्ष लगभग 80 अंडे देती है। इस नस्ल की प्रमुख किस्में जेट ब्लैक, पेन्सिल्ड और गोल्डेन है।

3. ग्रामप्रिया नस्ल: ग्रामप्रिया को भारत सरकार द्वारा हैदराबाद स्थित अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इसे खास तौर पर ग्रामीण किसान और जनजातीय कृषि विकल्पों के लिये विकसित गया है। इनका वजन 12 हफ्तों में 1.5 से 2 किलो होता है। इनके मीट का प्रयोग तंदूरी चिकन बनाने में अधिक किया जाता है। ग्रामप्रिया एक साल में औसतन 210 से 225 अण्डे देती है। इनके अण्डों का रंग भूरा होता है और उसका वजन 57 से 60 ग्राम होता है।

4. स्वरनाथ नस्ल: स्वरनाथ कर्नाटक पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान और विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा विकसित चिकन की एक नस्ल है। इन्हें घर के पीछे आसानी से पाला जा सकता है। ये 22 से 23 सप्ताह में पूर्ण परिपक्व हो जाती है। इनकी प्रतिवर्ष अण्डे उत्पादन करने की क्षमता लगभग 180-190 होती है।

1. डॉ.चन्द्रपाल सिंह सोलंकी, 2. डॉ.तृप्ति सिंह, 3. डॉ.ब्रजमोहन सिंह धाकड, 4. डॉ. अजय राय, 5. डॉ.मधु सिंह

1. विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र जशपुर, छग।
2. पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, रायगढ।
3. पशुचिकत्सा जनस्वास्थय और महामारी विज्ञान विभाग पशुचिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे. प.वि.वि. जबलपुर, मप्र।
4. पशुसूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग पशु चिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे.प.वि.वि. जबलपुर,मप्र।
5. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार-हरियाणा।

5. कामरूप नस्ल: यह बहुआयामी चिकन नस्ल है जिसे असम में कुक्कुट प्रजनन को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। यह नस्ल तीन अलग-अलग चिकन नस्लों का क्रॉस नस्ल है, असम स्थानीय(25%), रंगीन ब्रोइलर(25%) और ढेलम लाल(50%)। इसके नर चिकन का वजन 40 हफ्तों में 1.8-2.2 किलोग्राम होता है। इस नस्ल की प्रतिवर्ष अण्डे देने की क्षमता लगभग 118-130 होती है जिसका वजन लगभग 52 ग्राम होता है।

6. चिटागोंग नस्ल: यह नस्ल सबसे ऊँची नस्ल मानी जाती है। इसे मलय चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के मुर्गे 2.5 फिट तक लंबे तथा इनका वजन 4.5-5 किलोग्राम तक होता है। इनकी गर्दन और पैर बाकी नस्ल की अपेक्षा लंबे होते है। इस नस्ल की प्रतिवर्ष अण्डे देने की क्षमता लगभग 70-120 अण्डे है।

7. केरी श्यामा नस्ल: यह कड़कनाथ और कैरी लाल का एक क्रास नस्ल है। यह ज्यादातर मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पायी जाती है। यह 24 सप्ताह में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है और तब इनका वजन लगभग 1.2 किलोग्राम (मादा) तथा 1.5 किलोग्राम(नर) होता है। इनकी प्रजनन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 85 अण्डे होती है।

8. झारसीम नस्ल: यह झारखंड की मूल दोहरी उद्देश्य नस्ल है इसका नाम वहाँ की स्थानीय बोली से प्राप्त हुआ है। ये कम पोषण पर जीवित रहती है और तेजी से बढ़ती है। इस नस्ल की मुर्गियाँ उस क्षेत्र के जनजातीय आबादी के आय का स्रोत हैं। ये अपना पहला अण्डा 180 दिन पर देती है और प्रतिवर्ष 165-170 अण्डे देती है।

9. देवेंद्र नस्ल: यह एक दोहरी उद्देश्य चिकन है। यह पुरूष और रोड आइलैंडरेड के रूप में सिंथेटिकब्रायलर की एक क्रॉस नस्ल है। 12 सप्ताह में इसका शरीरिक वजन 1800 ग्राम होता है। 160 दिन में ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। इनकी वार्षिक अण्डा उत्पादन क्षमता 200 है। इसके अण्डे का वजन 54 ग्राम होता है।

10. श्रीनिधि: इस प्रजाति की भी मुर्गियां दोहरी उपयोगिता वाली होती हैं यह लगभग 210 से 230 अंडे तक देती है। इनका वजन 2.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक होता है। इन से अधिक मात्रा में मांस और अंडे दोनों के जरिए अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।

11. वनराजा: शुरुआत में मुर्गी पालन करने के लिए यह प्रजाति सबसे अच्छी मानी जाती है ये मुर्गी 3 महीने में 120 से 130 अंडे तक देती हैं और इसका वजन भी 2.5-5 किलो तक जाता है।

मुर्गी पालन का बढ़ता महत्व: आजकल देसी मुर्गी का पालन एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जो व्यक्ति को एक अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करता है। इसमें कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। भारत में दिन-प्रतिदिन देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय का प्रचलन बढ़ता जा रहा है भारत अंडों के उत्पाद में तीसरे नंबर पर और मांस के उत्पाद में पांचवें नंबर पर है।

प्राकृतिक खेती में मददगार देशी केंचुआ

क्या आपको पता है केंचुए खेती में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यदि देसी केंचुए नहीं होते तो शायद हरे-भरे जंगल और लहलहाते खेत भी नहीं होते। आज के समय में जब हानिकारक केमिकल वाली खेती की बजाय प्राकृतिक खेती पर ज़ोर दिया जा रहा है, देसी केंचुए की भूमिका और बढ़ जाती है। यह कुदरती तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके इसे अधिक उपजाऊ बनाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि वर्मीकंपोस्ट तैयार करने वाले जीव भी केंचुए होते हैं, लेकिन वास्तव में वह देसी केंचुए न होकर अफ्रीकन केंचुए हैं, जिन्हें आयसेनिया फिटिडा कहा जाता है। यदि आप कुदरती तरीके से खेती करने की सोच रहे हैं, तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि खेत में मिट्टी को अधिक उपजाऊ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए देशी केंचुए बहुत जरूरी हैं।

अक्सर लोग वर्मीकंपोस्ट को केंचुए वाली खाद कहते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जीव देशी केंचुआ न होकर अफ्रीकन अर्थवॉर्म यानी आयसेनिया फिटिडा होता है। केंचुए को अंग्रेजी में अर्थवॉर्म कहा जाता है। वैसे तो ऑर्गेनिक खेती में वर्मीकंपोस्ट का खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कृषि जानकार देशी केंचुए को ज्यादा फायदेमंद बताते हैं। महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित सुभाष पालेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, पानी, दलहन, आटा और जंगल की मिट्टी से बने जीवामृत के इस्तेमाल से जमीन में केंचुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

देशी केंचुआ बनाम अफ्रीकन केंचुआ: देशी केंचुआ और आयसेनिया फिटिडा अलग-अलग होते हैं। कृषि जानकारों के मुताबिक, देशी केंचुआ में 16 लक्षण होते हैं, जबकि आयसे, निया फिटिडा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं होते हैं। देशी केंचुआ मिट्टी खाता है, जबकि आयसेनिया फिटिडा गोबर खाता है। देसी केंचुआ जमीन में अनगिनत छेद करता है जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर जमा होता जाता है। इसके विपरीत, आयसेनिया फिटिडा जमीन के ऊपर ही अपना काम करता है। यदि खाना नहीं मिलता है तो देशी केंचुआ खेत से भागता नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर चला जाता है, जबकि आयसेनिया फिटिडा खाना न मिलने पर दूसरे खेत में चला जाएगा।

देशी केंचुए की खासियत: देशी केंचुआ जमीन में मिट्टी खाते-खाते गहराई तक चला जाता है और ऊपर आने के लिए दूसरा छेद करता है। इससे जमीन में अनगिनत छेद हो जाते हैं। इनकी बदौलत पौधों की जड़ों को गहराई तक पानी और पोषण मिलता रहता है जिससे पौधों का विकास अच्छी तरह होता है। केंचुआ जमीन से ऊपर-नीचे करते समय एक तरह पदार्थ छेद की दीवार पर लगा देता है, जिससे वह बंद नहीं होता। इस पदार्थ को वर्मी वॉश कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो जड़ों के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, केंचुआ कच्ची चट्टान, रेत कण और मिट्टी खाते-खाते ज़मीन के अंदर जाकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को भी खा जाता है। यानी केंचुआ फसलों को बीमारी से बचाने में भी मददगार है। केंचुओं को 24 घंटे काम करने के लिए सूक्ष्म पर्यावरण का होना जरूरी है।

देशी केंचुओं के लिए उपयुक्त वातावरण: अब आप सोच रहे होंगे कि यह सूक्ष्म पर्यावरण क्या है, तो आपको बता दें कि दो पौधों के बीच हवा आती जाती रहे और मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, यही सूक्ष्म पर्यावरण है। सूक्ष्म पर्यावरण के निर्माण के लिए खेत में पेड़-पौधों की 2 कतारों के बीच फसलों के अवशेषों को फैलाकर रख दें, बस केंचुआ अपने काम पर लग जाएगा। यदि आप भी प्राकृतिक तरीके से अधिक फसल उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसान खेत में देशी केंचुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें।

कृषि अर्थव्यवस्था पर काम करने वाले प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर सेन

प्रो. अभिजित सेन ऐसे प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ज्यादातर ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था पर काम किया। उन्होंने नीति निर्माण करने वाले देश के कई शोध स्तरीय निकायों में कार्य किया। यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के चेयरमैन और पूरे 10 साल तक योजना आयोग के पूर्णकालिक सदस्य (कृषि) रहे। प्रो. सेन 14वें वित्त आयोग के भी सदस्य थे। इसके अलावा उन्होंने कई उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की, जैसे खाद्यान्न पर दीर्घकालिक नीति के संबंध में उच्च स्तरीय समिति, वायदा कारोबार पर समिति आदि। उन्होंने कृषि की लागत के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए किसानों की आय का अनुमान तैयार किया और अपने कार्यों को एमएस भाटिया के साथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया।

मुझे 11वीं (2007-2012) और 12वीं (2012-2017) पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकारी समूहों और संचालन समितियों में 10 साल से अधिक समय तक प्रो. सेन के साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला था।

प्रो. सेन को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तैयार करने के लिए भी राज्यों द्वारा याद किया जाता है, जिसने शायद पहली बार राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत दिया गया धन खर्च करने के लिए सुगमता प्रदान की थी। जब मैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तब मैंने एक ब्लाइड पर काम किया था, जिसमें दिखाया गया था कि जब कृषि के मामले में व्यापार की शर्तों में इजाफा हुआ, तो भारत में कृषि विकास में तेजी आई और टीओटी में कमी आने पर गिरावट आई। इसका मतलब यह था कि कीमतें कृषि में विकास का संचालन कर रही थीं और इनका इस क्षेत्र की समृद्धि से सीधा संबंध था। प्रो. सेन ने अपने अनोखे तरीके से चुटकी ली थी कि आपका अनुमान बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं इसका खंडन नहीं कर सकता।' प्रो. सेन खाद्य नीति और मूल्य समर्थन प्रणालियों में सार्वजनिक हस्तक्षेप के प्रबल समर्थक थे।

डॉ. रमेश चंद,
सदस्य, नीति आयोग

मुरैना में मकान, पशुहानि के के लिए 3.20 करोड़ रुपए की बांटी राहत

किसानों को अभी तक नहीं मिला फसल नुकसान का मुआवजा

» सर्वे में 13904 किसानों की 7637 हेक्टेयर फसल प्रभावित

मुरैना। जागत गांव हमार

चंबल नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए ग्रामीणों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ में क्षतिग्रस्त घर, पशुघर, मवेशियों की मौत और गृहस्थी की सामग्री के नुकसान का मुआवजा 3865 परिवारों को तीन करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा अब तक बांट दिया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। बाढ़ के बाद प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे और मुआवजा वितरण के आंकड़ों में अंतर आ गया है। सर्वे में 3451 मकानों को नुकसान माना था, लेकिन मुआवजा वितरण हुआ तो क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या घटकर 2406 रह गई है। सर्वे के आकड़ों में 109 पशुओं की मौत मानी गई थी, लेकिन मुआवजा बंटा तो केवल 4 पशुओं की क्षति का मुआवजा बांटा गया है। इसके इतर सर्वे में एक भी पशुघर को बाढ़ से नुकसान नहीं माना, लेकिन मुआवजा बंटा तो 149 पशुघर बाढ़ में बहना बता दिए गए हैं, इनका 3.12 लाख से ज्यादा का मुआवजा बंटा है। इसके अलावा बाढ़ में में चंबल नदी बाढ़ में 3865 परिवारों का नुकसान माना है। जिला प्रशासन ने ऐसे हर परिवार को पांच-पांच हजार रुपए का मुआवजा गृहस्थी के सामान और 50-50 किलो राशन भी दिया है। लेकिन फसलों के नुकसान का मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला। जिला प्रशासन के सर्वे में 13904 किसानों की 7637 हेक्टेयर फसल को बाढ़ प्रभावित माना था।

बाढ़ का कहर अंबाह में ज्यादा

चंबल नदी की बाढ़ का कहर अंबाह तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा गांव अंबाह में खाली कराए गए थे और सबसे बड़ा राहत शिविर भी अंबाह में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अंबाह क्षेत्र या फिर सबलगढ़ के रतियापुरा का दौरा किया था। हर स्तर पर अंबाह में बाढ़ को चिंतानजक माना गया, लेकिन जब मुआवजा बंटा तो अंबाह से ज्यादा जौरा तहसील में बांटा गया है। कुल 149 पशुघर बाढ़ में बहना बताया, जिसमें से 147 पशुघर जौरा तहसील के हैं, अंबाह व सबलगढ़ में एक भी पशुघर को नुकसान नहीं माना गया। इसी तरह बाढ़ से सबसे ज्यादा 766 घरों को नुकसान भी जौरा में माना गया है, जबकि अंबाह के 712 घरों को नुकसान माना गया है।

एक नजर में कहां कितना हुआ नुकसान

तहसील	घर	पशुघर	मवेशी	राशन	5000 की सहायता
पोरसा	514	0	0	1319	896
अंबाह	712	0	2	2761	1461
मुरैना	25	2	2	25	25
जौरा	766	147	0	1300	1103
सबलगढ़	389	0	0	4589	380
कुल	2406	149	04	9994	3865

सभी को पता है, कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान अंबाह तहसील में हुआ है, लेकिन सर्वे में जौरा में सबसे ज्यादा नुकसान बताया गया है, इसका कारण तो अफसर ही जानें। मैंने पिछले दिनों महापौर चुनाव में हार के लिए कलेक्टर-एसपी को जिम्मेदार बताया था, हो सकता है इसका असर भी अंबाह तहसील के सर्वे में पड़ा है। अंबाह में भी कई पशु घर गिरे, मवेशी मरे हैं, लेकिन एक भी पशुघर की क्षति का मुआवजा नहीं मिला।
कमलेश जाटव, विधायक अंबाह

बाढ़ पीड़ितों की गृहस्थी के नुकसान, मकानों की क्षति, पशुघर क्षति, मवेशियों की मौत आदि का मुआवजा सभी प्रभावितों को बांट दिया गया है। मुआवजा में किसी भी प्रभावित को नहीं छोड़ा गया है। फसलों के नुकसान का अंतिम सर्वे चल रहा है, जल्द ही फसल नुकसान का मुआवजा भी किसानों के खाते में जमा करा दिया जाएगा।
नरोत्तम भार्गव, अपर कलेक्टर, मुरैना

चरनोई भूमि विकास मिशन का होगा गठन

भोपाल। मध्य प्रदेश में गौवंश के चारा प्रबंधन के लिए चरनोई भूमि विकास मिशन का गठन किया जा रहा है, जो राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करेगा। वहीं, निगरानी का जिम्मा मप्र गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का होगा। बोर्ड ने मिशन के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद प्रदेशभर में खाली चरनोई भूमि का प्रबंधन शुरू होगा। बोर्ड इस भूमि पर चारा उगाएगा और प्रदेश की 2200 गौ-शालाओं को देगा। दो माह पहले बोर्ड की कार्यपरिषद की बैठक में यह मुद्दा आया था। कार्यपरिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने चारा संकट का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिशन के गठन का अनुरोध किया था। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में चरनोई भूमि को चिह्नित कर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और उस पर नेपियर सहित विभिन्न प्रजाति की घास उगाई जाएगी। यदि सरकार की कोई एजेंसी घास उगाने को तैयार नहीं हुई, तो इस क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को यह काम ठेके पर दिया जाएगा।

प्रदेश में 2200 गौ-शाला: वर्तमान में प्रदेश में 2200 गौ-शाला हैं। इनमें से 1665 संचालित हैं। इनमें से 627 स्वयंसेवक संगठन चला रहे हैं। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने बताया कि वर्तमान में 14 से 15 रुपए किलो की दर से चारा मिल रहा है। इस खर्च को कम करने के लिए मिशन का गठन जरूरी है।

तीन महीने में सभी 313 विकासखंडों में गौ एंबुलेंस

सड़कों पर बैठे गौ-वंश के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उपचार के लिए अत्याधुनिक गौ एंबुलेंस तीन माह में आ जाएगी। सभी 313 विकासखंडों में एक-एक एंबुलेंस दी जाएगी। हाल ही में स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने बोर्ड के अंतर्गत जिलों में गठित समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक का सिलसिला छिंदवाड़ा से शुरू हुआ है। स्वामी ने बताया कि एंबुलेंस के लिए शासन से राशि मिल चुकी है। गायों के पालन, संरक्षण, संवर्धन के लिए जनभागीदारी से संचालित कार्ययोजना में महिला स्वसहायता समूहों की मदद ली जाएगी। वहीं गौशालाओं की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा।

मालवा-निमाड़ अंचल में लंपी का प्रकोप, खंडवा में 544, बुरहानपुर में 486 मवेशी चपेट में, सीएम शिवराज का निर्देश

दूसरे राज्यों से मप्र आने वाले पशुओं पर लगाओ प्रतिबंध

भोपाल/इंदौर। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी से प्रदेश में पशुओं की मृत्यु ना हो। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। बीमारी प्रभावित जिलों से लगे जिलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य राज्यों से आ रहे पशुओं पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। लंपी बीमारी से बचाव के लिए अधिक से अधिक पशुओं में आवश्यक टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

पशु पालकों को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी करें। मुख्यमंत्री लंपी स्किन बीमारी की प्रदेश में स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। निवास कार्यालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पशुपालन जेएन कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास अजीत केसरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल में कंट्रोल रूम स्थापित लंपी स्किन बीमारी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित ग्रामों और जिलों में पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बीमारी और उससे बचाव के संबंध में जागरूकता के लिए वेबीनार, मीटिंग और राज्य स्तरीय युवा संवाद किए जा रहे हैं। प्रदेश के संपूर्ण चिकित्सा अमले को अलर्ट मोड पर रखा गया है और केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

खंडवा जिले के पंधाना व खालवा ब्लाक लंपी का प्रभाव अधिक

मालवा-निमाड़ में लंपी स्किन वायरस का दायरा बढ़ा है। खंडवा के 20 गांवों में 544, बुरहानपुर में 486 और रतलाम में 413 मवेशी प्रभावित हुए। मौतें भी हुई हैं। हालांकि स्वस्थ होने की दर अधिक है। टीका की कमी जरूर सामने आ रही है। खंडवा जिले के पंधाना व खालवा ब्लाक लंपी स्किन वायरस का प्रभाव अधिक है। संक्रमित 544 मवेशी में से छह की मौत हुई है। गोट पाक्स वैक्सीन की 18250 डोज उपलब्ध हैं। अभी तक 11286 डोज लगाई जा चुकी हैं। पांच हजार डोज की मांग भेजी गई है। बुरहानपुर में पांच गोवंश की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पांच हजार टीका मंगाए थे। इनमें से तीन हजार स्वस्थ गौ वंशी को लगाए जा चुके हैं। इस बीच दस हजार और टीकों का मांग भेजी गई है। बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र में एक गाय में वायरस का प्रभाव मिला है। रतलाम जिले में 407 मवेशी स्वस्थ हो गए और एक की मौत हो गई। शेष का उपचार चल रहा है। 36900 टीका की खेप मिली थी। इसमें से 29100 टीका लगाए जा चुके हैं। दूध की आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं देखा गया है। संक्रमित गौवंशी की स्वस्थ होने की दर 95 प्रतिशत है। मंदसौर जिले में 95 गांवों में संक्रमित 181 गोवंशी में से 124 स्वस्थ हो चुके हैं।

जरूरतमंद किसानों से 19 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन

11 कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही अनुदान, करें आवेदन

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती को आसान बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास में जुटी है। इसी कडी में मप्र सरकार किसानों छूट पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। सरकार ने 11 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा राज्य के सभी वर्ग के किसानों से 11 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन 8 सितम्बर के दोपहर 12 बजे से 19 सितम्बर 2022 तक कर सकते हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए इस दौरान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान- मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कृषि विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों को दो भागों में रखा गया है। पहले भाग के कृषि यंत्रों के लिए जिले वार लक्ष्य पहले से तय किए गए हैं, जिनके विरुद्ध किसान आवेदन कर सकते हैं तथा दूसरे तरह के कृषि यंत्रों को मांग के अनुसार रखा गया है अर्थात किसानों के द्वारा किए गए आवेदनों के अनुसार इन कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए जाएंगे।

कृषि यंत्रों पर दिया जाने वाला अनुदान

किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को कई प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा किसान वर्ग के अनुसार होती है, जो की 40 से 50 प्रतिशत तक है। राज्य में एक किसान को किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी यह जानकारी किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्क्युलेटर पर देख सकते हैं।

किसानों को जमा करना होगा बैंक ड्राफ्ट

ऊपर दिये हुए सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। जहां सभी कृषि यंत्र के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि 5000 रुपए निर्धारित की गई है वहीं केवल रीपर कम बाइंडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट की धरोहर राशि 10,000 रुपए है। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन नहीं होता है तो यह धरोहर राशि किसानों को लौटा दी जाएगी परंतु चयन होने के बाद यदि किसान कृषि यंत्र नहीं खरीदता है तो यह धरोहर राशि उस किसान को नहीं दी जाएगी।

इन कृषि यंत्रों के लिए जारी किए गए हैं अनुदान के लिए लक्ष्य

इसके अंतर्गत 6 प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। किसान इन सभी कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह कृषि यंत्र इस प्रकार है-

- विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड)
- स्वचलित रीपर/रीपर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड)
- पॉवर टिलर- 8 बीएचपी से अधिक
- श्रेडर / मल्चर
- पावर वीडर (2 बीएचपी से अधिक का इंजन चलित)
- रीपर कम बाइंडर
- यह भी पढ-50 प्रतिशत की सब्सिडी पर सिंचाई के लिए गहरी बोरिंग करवाएं
- ऑन डिमांड के तहत किसान इन कृषि यंत्रों के लिए कर सकते हैं आवेदन
- बेलर
- हे रेक
- हैप्पी सीडर/ सुपर सीडर
- न्यूमेटिक प्लांटर
- पावर हैरो

कहां करें आवेदन कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन के बाद ही जारी लक्ष्य के अनुसार किसानों का चयन किया जाएगा। मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान ऑनलाइन कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु किसानों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

सरकार किसानों को 55 प्रतिशत सब्सिडी पर दे रही है ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश भर में चलाई जा रही है, विशेषकर जहां पानी की कमी अधिक है वहां पर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा योजना के अलग-अलग घटक तैयार किए गए हैं। जिसके तहत किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं अन्य सिंचाई यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक अटल भूजल योजना के तहत राज्य के चयनित जिलों के किसानों से ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। राज्य के इच्छुक किसानों के लिए जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन 09 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। अटल भूजल योजना के तहत के तहत वर्ष 2022-23 के लिए ड्रीप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर का आवेदन प्रदेश के 6 जिलों के 9 विकासखंडों में सभी वर्गों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है।

योजना के अंतर्गत सागर जिले के सागर विकासखंड, दमोह जिले पथरिया विकासखंड, पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड, छतरपुर जिले के छतरपुर, नौगांव, राजनगर विकासखंड, टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़, पलेरा विकासखंड एवं निवाड़ी जिले के निवाड़ी विकासखंड के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट पर दिया जाने वाला अनुदान

किसानों को ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत ही अनुदान दिया जायेगा। जिसके अनुसार सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत अनुदान एवं सभी वर्ग के बड़े किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

अनुदान के लिए आवेदन यहां करें

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय अपने पास फोटो, आधार, खसरा नम्बर/बी1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा। इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpf-sts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

केंद्र सरकार ने मूंग और उड़द की खरीद सीमा में की वृद्धि

अब एक दिन में बेच सकेंगे 40 क्विंटल मूंग और उड़द

भोपाल। देश में सरकार द्वारा दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मूंग एवं उड़द जैसी दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों से मूंग एवं उड़द फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इस कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश में किसानों के लिए जायद (गर्मी) सीजन 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएमएस) के अंतर्गत मूंग और उड़द की खरीद की सीमा में वृद्धि कर दी है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की थी। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर मप्र के किसानों के लिए छूट की सीमा को मंजूरी दी गई है। किसान अब एक दिन में बेच सकेंगे 40 क्विंटल मूंग एवं उड़द

ऐसे किसान जिनकी 25 क्विंटल की तुलाई हो चुकी है, परंतु जिनके पास अभी पात्रता अनुसार उपार्जन के लिए मात्रा शेष है उनका कृषक के आवेदन पर निर्धारित जानकारी प्राप्त करने पर द्वितीय एसएमएस किया जाएगा। साथ में उसके शेष स्टाक का भौतिक सत्यापन जिलों द्वारा किया जायेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मूंग एवं उड़द की एक दिन की उपार्जन सीमा को बढ़ाने से बहुत राहत मिलेगी। इससे किसानों का आवागमन एवं ईंधन में होने वाला व्यय और समय दोनों ही बचेंगे।

सब्सिडी पर ट्रैक्टर और पॉवर टिलर चलित कृषि यंत्र लेने किसान करें आवेदन

भोपाल। देश में कृषि लागत कम करने एवं फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिक से अधिक किसान इन कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सके इसके लिए सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों से भूमि विकास, जुताई, रोपाई और खुदाई करने वाले कृषि यंत्र एवं उपकरणों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध 8 सितंबर 2022 के दिन सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के किसानों से बागवानी कार्यों के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण-20 एचपी से कम, प्लास्टिक मल्च लगाने वाला उपकरण, यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर-(क्षमता 16 लीटर) आदि पर अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए हैं इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत बागवानी के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत ट्रैक्टर

20 एचपी सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 75 हजार रुपए का अनुदान वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

इसी तरह राज्य के किसानों को योजना के तहत ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित उपकरण-20 एचपी से कम भूमि विकास, जुताई रोपाई और खुदाई के लिए आवश्यक कृषि उपकरणों पर सामान्य वर्ग के किसानों को जिसकी इकाई लागत 30 हजार रुपए तक पर 40 प्रतिशत अधिकतम 12 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाएगा। वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

प्लास्टिक मल्च पर दिया जाने वाला अनुदान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित (20 एचपी से कम) प्लास्टिक मल्च लागने वाले उपकरण पर सामान्य वर्ग के किसानों को निर्धारित इकाई लागत 70 हजार रुपए पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 28 हजार रुपए का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है। वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 35 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/ विद्यत चलित स्प्रेयर पर दिया जाने वाला अनुदान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन एमआईडीएच योजना के घटक कृषि यंत्रीकरण के तहत यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर पर सामान्य वर्ग के किसानों को निर्धारित इकाई लागत 20 हजार रुपए पर 40 प्रतिशत अधिकतम 8 हजार रुपए का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है। वहीं लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपए तक का अनुदान प्रति यंत्र दिया जाता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र नीमच में बकरी पालन पर प्रशिक्षण

नीमच । कृषि विज्ञान केन्द्र, नीमच में गतदिनों आर्या योजनांतर्गत ग्रामीण युवाओं हेतु बकरी पालन को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य हेतु सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के नीमच, जावद, मनासा विकासखण्ड के किसानों एवं ग्रामीण युवकों ने अपना पंजीयन कराया एवं प्रशिक्षण का लाभ लिया। कार्यक्रम में केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. सी. पी. पचौरी ने कार्यक्रम उद्देश्य एवं महत्व की जानकारी देते हुए बकरी पालन, बकरियों की प्रजातियों, बकरियों की आवास व्यवस्था, बकरी स्वास्थ्य प्रबंधन आदि की तकनीकियों के बारे में जानकारी दी। तकनीकी सत्र में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. पी. एस. नरूका, डॉ. शिल्पी वर्मा, डॉ. श्यामसिंह सारंगदेवोत ने बकरी पालन एवं डॉ. जे. पी. सिंह द्वारा जैविक खेती पर जानकारी दी। पशुपालन विभाग के डॉ. के. के. शर्मा, डॉ. ए. आर. धाकड़ एवं डॉ. एस. के. शर्मा, पशुचिकित्सक ने भी बकरी पालन पर जानकारी दी।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. जी.एस.गाठिये को 'वेस्ट कृषि विस्तार वैज्ञानिक अवॉर्ड'

धार । कृषि विज्ञान केन्द्र, धार में पदस्थ, कृषि वैज्ञानिक डॉ. जी.एस.गाठिये को धार जिले में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट विस्तार एवं अनुसंधान कार्य हेतु नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, कमल पटेल, कृषि मंत्री मप्र शासन, के द्वारा ''वेस्ट कृषि विस्तार वैज्ञानिक अवॉर्ड-2022'' 11वीं राष्ट्रीय बीज अधिवेशन के दौरान राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में दिया गया।

सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के लिए जगदीश साहू पुरस्कृत

बैतूल । स्वतंत्रता दिवस पर आत्मा अंतर्गत बैतूल के प्रभातपट्टन में कृषकों को पुरस्कृत किया गया जिसमें जिला स्तर पर कृषि में ग्राम गेहं बारसा के उन्नत कृषक जगदीश प्रसाद साहू को सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन में पुरस्कार प्रदान किया गया एवं विकासखंड स्तर पर उद्यानिकी में नारायण हारोड़े चन्दोरा, पशुपालन में दयाराम सोलंकी पचधार को पुरस्कृत किया गया। आजादी के स्वर्णिम 75 वर्ष अमृत महोत्सव में ध्वजारोहण पश्चात आत्मा समिति के चेयरमैन पंधरीनाथ पाटनकर के द्वारा अन्य कृषकों को भी पुरस्कार दिया गया । इस अवसर पर जगदीश प्रसाद साहू ने प्राकृतिक कृषि के फायदे बताए और अपने अनुभव साँझा किए । एसएडीओ संगीता मवासे, बीटीएम जयप्रकाश लोखंडे, एटीएम घनश्याम भिंडोंडे, आरएईओ दीपिका पवार, नंदकिशोर गुहे, प्रवीण अतुलकर, हिमांशु उकंडे, आयुष साहू आदि ने सभी कृषकों को बधाई दी एवं श्री हारोड़े ने सब्ज़ी उत्पादन एवं सोलंकी ने पशुपालन के महत्व को बताया।

भोपाल में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश का पहला बकरी पालक सम्मेलन

अब बकरी पालन भी व्यवसाय के रूप में पंजीकृत किया जायेगा

बकरी पालन करें और अच्छी आय अर्जित करें: मंत्री पटेल

भोपाल। जागत गांव हमार

बकरी उपयोगी पालतू पशु है। बकरियों के मध्य रहने से टीबी का मरीज ठीक हो जाता है। नींबू वृक्षों में बकरी मल का प्रयोग बम्पर क्रॉप देता है। बहुत कम स्थान में पलने वाली बकरी के माँस, खाल, दूध सभी से बकरी पालक को आय होती है। 6 सितम्बर को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भोपाल में प्रदेश के पहले बकरी पालन को प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास हेतु पशुपालक सम्मेलन का शुभारंभ कर संबोधित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आधुनिक तकनीक अपना कर पशुपालन विभाग के सहयोग से बकरी पालन करें और अच्छी आय अर्जित करें। उन्होंने बकरी पालकों को बैंक ऋण लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया। प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ तरूण राठी और राज्य कुक्कुट विकास निगम एवं पशुधन एच.बी.एस. भदौरिया भी मौजूद थे।

कृत्रिम गर्भाधान योजना

अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि बकरी उत्पाद की माँग बाजार में बढ़ रही है। प्रदेश में उच्च नस्ल के बकरी वंश को बढ़ाने के लिये कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चिन्हित जिलों से आरंभ कर जल्द ही पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन और समय पर टीकाकरण, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। श्री कंसोटिया ने सम्मेलन में भाग ले रहे विषय-विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और बकरी पालकों से कहा कि परम्परागत गेहूँ, मक्का, गुड़ के विकल्प में बकरी का चारा तैयार करने पर मंथन करें। श्री कंसोटिया ने बताया कि कुक्कुट व्यवसाय को पिछले साल से पंजीकृत किया जा रहा है। अब बकरी पालन को भी पंजीकृत किया जायेगा।

प्रदेश में बकरी संख्या 38 प्रतिशत बढ़ी

संचालक डॉ. आर.के मेहिया ने कहा कि प्रदेश में पिछली पशु गणना के मुकाबले बकरी संख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि बकरी पालन के प्रति लोगों में रूझान बढ़ा है। कार्यक्रम में पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉ. मुकुल आनंद और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्व विद्यालय के विषय-विशेषज्ञों ने भी बकरी पालन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पिछले 22 साल से बकरी व्यवसाय कर रहे धार के दीपक पाटीदार और देश-विदेश में नौकरी कर चुके टेलीकॉम इंजीनियर से आज सफल बकरी पालक बन चुके भोपाल के हेमंत माथुर ने रोचक ढंग से अपनी सफलता की कहानियां साझा की। प्रदेश भर से आये पशुपालकों के प्रश्नों का भी समाधान कार्यक्रम में किया गया। उप संचालक डॉ. अनुपम अग्रवाल ने संचालन किया और संयुक्त संचालक डॉ. पटेल ने आभार माना।

बकरी पालन में मप्र देश में पांचवें स्थान पर

बेटनरी काउंसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि बकरी पालन में मप्र देश में पांचवें स्थान पर और विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। बकरी की उच्च नस्ल के लिये कृत्रिम गर्भाधान बहुत जरूरी है। अच्छी नस्ल का बकरा एक से डेढ़ लाख रूपये में मिलता है। कृत्रिम गर्भाधान से पालक को यह सुविधा हिमीकृत स्ट्रॉ से मात्र 70 रूपये में उपलब्ध हो जायेगी।

अतिथियों का स्वागत मुनगा के पौधे देकर किया गया

कृषि विज्ञान केन्द्र बैतूल में पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बैतूल। कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल बाजार और महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल के संयुक्त तत्वधान मे कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल बाजार के सभाकक्ष मे पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप में दुर्गावती वर्मा अध्यक्षा, नगर परिषद् बैतूल बाजार, बैतूल उपस्थित रहे। साथ ही वंदना धुर्वे, दिव्या वर्मा, नीतू राठौर पार्षद, बैतूल बाजार उपस्थित थीं और महिला एवं बाल विकास विभाग से नीरजा शर्मा बैतूल ग्रामीण, आंगनवाडी पर्यवेक्षक और आंगनवाडी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों का स्वागत मुनगा के पौधे देकर किया गया।

अतिथियों के आगमन के पश्चात् केन्द्र प्रमुख डॉ. व्ही. के. वर्मा द्वारा इस वर्ष पोषण माह की थीम महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चों और शिक्षा के बारे मे बताते हुये पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता के विस्तृत जानकारी दी साथ ही आहार मे मुनगे के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात् कृषि विज्ञान केन्द्र के डॉ. मुरलीधर इंगले कार्यक्रम सहायक (खाद्य विज्ञान) ने पोषण आहार, पोषण माह की शुरूवात तथा महिलाओं और किशोरियों मे संतुलित आहार का महत्व बताते हुये पोषण माह कार्यक्रम को पुरे साल भर चलाये जाने के लिये अतिथियों से कहा।

इस कार्यक्रम के अंत मे द्वारा सभी सम्मानित आगन्तुकों का आभार प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में 48 महिलायें एवं 26 छात्राएं तथा केन्द्र के सभी वैज्ञानिक डॉ. शैलेन्द्रसिंह गौतम, आर. डी. बारपेटे, डॉ. मेघा दुबे, डॉ. संजय जैन, नेपाल बारस्कर, सौरभ मकवाना और राजू सलामे ने सक्रिय रूप से शामिल हुए।

किसानों को प्रशिक्षित करने केवीके देवास में मास्टर का प्रशिक्षण आयोजित

देवास। जलवायु आधारित कृषि के अंतर्गत आईटीसी मिशन सुनहरा कल द्वारा एनसीएचएसई संस्था के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र देवास में आज मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जिले में मास्टर ट्रेनर तैयार कर जिले के कृषि विभाग के अमले के माध्यम से ग्राम स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षित करके कृषि उत्पादन लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि करना है । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप संचालक कृषि आर.पी.कनेरिया थे।

श्री कनेरिया के उद्बोधन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात् केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ . ए.के.बड़ाया ने जिले की मुख्य फसलों जैसे सोयाबीन, चना एवं गेहूं की उन्नत उत्पादन तकनीकी पर प्रकाश डाला। केन्द्र के शस्य वैज्ञानिक डॉ .महेन्द्र सिंह द्वारा सोयाबीन फसल के विपुल उत्पादन पर तकनीकी सत्र लिया गया। देवास जिले के सभी प्रशिक्षणार्थियों कृषि विकास अधिकारी, आत्मा परियोजना के विकासखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक को खरीफ की फसल सोयाबीन के लिये तकनीकी प्रशिक्षण सहायक संचालक कृषि जगदीश ठाकुर, लोकेश गंगराडे आई. टी. सी.मिशन सुनहरा कल एवं एनसीएचएसई केअधिकारीगण के साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र, देवास के वैज्ञानिक डॉ. के.एस.भार्गव, डा. निशीथ गुप्ता, डॉ महेन्द्र सिंह, डॉ मनीष कुमार, डॉ लक्ष्मी, नीरजा पटेल, श्रीमती अंकिता पाण्डेय एवं डॉ सविता कुमारी द्वारा दिया गया।

जनता दरबार लगाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुनी बाढ़ प्रभावित ग्रामीणें की समस्या, बोले

किसान अपने बाढ़ प्रभावित खेतों को खुद समतल करें और सरकार 194 रुपए प्रतिदिन देगी मजदूरी

शिवपुरी/श्योपुर। लेमराज मौर्य

बाढ़ के कारण कई खेतों में रेत आ जाने की समस्या निर्मित हुई है। अपने खेतों में रेत हटाने और उसे समतलीकरण कर उपजाऊ बनाने का काम किसान खुद करें, सरकार उन्हें प्रतिदिन 194 रुपए मनरेगा मद से मजदूरी देगी। यह बात केन्द्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने बाढ़ प्रभावित जैनी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। केन्द्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी और मौके पर ही निराकरण के निर्देश कलेक्टर को दिए। केन्द्रीय मंत्री ने जैनी, तलावदा, सामरसा आदि गांवों में पहुंचकर वहां समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मिली समस्याओं के निराकरण के निर्देश मौके पर मौजूद कलेक्टर शिवम वर्मा को दिए। जनता दरबार में सबसे अधिक समस्या बाढ़ से खेतों में बजरी आ जाने की मिली। किसानों ने बताया कि बजरी आ जाने से खेत उपजाऊ नहीं रहे। केन्द्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि अपने खेतों में बजरी हटाने के लिए वह खुद मजदूरी करें या दूसरे मजदूर लगाए। एक दिन एक मजदूर के मनरेगा से 194 रूपए मिलेंगे। आप अपने खुद के खेतों में काम करें और मजदूरी सरकार से पाए, खेत को उपजाऊ बनाएं।

इस दौरान प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाह, विजयपुर विधायक सीताराम आदिवासी, जिपं अध्यक्ष गुड्डी बाई, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया, जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह जाट, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, बृजराज सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

इन शिकायतों का हुआ मौके पर निराकरण

- एक ग्रामीण ने बताया कि राहत राशि वितरण में भेदभाव किया जाता हैं। यह विगत वर्ष देखा गया।
- केन्द्रीय मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि, सहायता पाने वाले हितग्राहियों की सूची पंचायत पर चस्पा करें।
- ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्रपाल बाबा की सड़क भी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। भक्तों को परेशानी हो रही है। इस पर केन्द्रीय मंत्री ने कलेक्टर को दोबारा सड़क बनवाने के निर्देश मौके पर ही दिए।
- ग्रामीण ने कहा कि यूरिया और डीएपी का संकट बढ़ गया हैं। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इस पर केन्द्रीय मंत्री के पूछने पर कलेक्टर ने बताया कि बाढ़ की वजह से रास्ते बंद होने और सोसायटियों के उठाव नहीं करने से समस्या थी, जो दूर कर ली गई हैं।
- ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चंबल पार्वती का पानी सड़कों के ऊंचाई अधिक हो जाने से भरा हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि इस मामले में कुछ हो सकता है तो किया जाए।
- खाद को सस्ता करने की मांग पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हम हर वर्ष किसानों को सब्सिडी पर खाद उपलब्ध कराने के लिए दो लाख करोड़ की सब्सिडी देते हैं, जो बहुत बड़ी बात हैं।

फिर क्षेत्र में लौटेगी गिर नस्ल की गाय

गोरस में गौमाता नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हमारे क्षेत्र में गिर नस्ल की गायों की बहुतायात थी। हम देश-प्रदेश में गिर गाय नस्ल के मामले में बहुत आगे थे, लेकिन लापरवाही के चलते यह नस्ल बर्बाद हो गई हैं। अब इस नस्ल को दोबारा से बढ़ाने के लिए गौमाता नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया हैं। केन्द्र सरकार के इस कार्यक्रम को राज्य सरकार एनआरएलएम के माध्यम से मालव कंपनी बनाई है। यह कंपनी पशुपालकों को उनका दूध और दूसरे उत्पादनों का भरपूर पैसा दिलाएगी। पशुपालकों को गाय का दूध बेचने के लिए भटकना न पड़े इसके लिए शिवपुरी चिलर प्लांट खोला जा रहा हैं। चारा इत्यादि की व्यवस्था भी होगी। कुल मिलाकर गाय अब पशुपालकों पर बोझ नहीं बल्कि उनका सहारा बनेगी।

हेलीकॉप्टर वाले नहीं पैदल वालेहमारे मंत्री

गौमाता नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे केन्द्रीय मंत्री के सम्मान में स्थानीय विधायक सीताराम आदिवासी के भाषण दिनभर चर्चा में रहे। सीताराम ने कहा कि हमारे मंत्री हेलीकॉप्टर वाले नहीं पैदल चलने वाले हैं। वह हर माह श्योपुर आते हैं और सभी की समस्या सुनते है, ऐसा मंत्री हमें जिंदगी में नहीं मिलेगा। लोग सीताराम के इस भाषण को कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर श्योपुर आए केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़कर देख रहे हैं।

अवैध वसूली पर 8 एनजीओ ब्लैक लिस्टेड, केंद्रीय टीम का प्रशासन ने नहीं किया सहयोग

रीवा में गौशालाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा

धनंजय तिवारी। जागत गांव हमार

रीवा। जिले में गौ शाला के नाम पर अवैध वसूली के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। बात इतनी बढ़ गयी है कि केन्द्रीय पशु कल्याण विभाग के सदस्य यहां जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने गौ शालाओं की जांच की और 8 को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। यहां डिस्पेंसरी के नाम पर फंड वसूला जा रहा था। रीवा जिले में गौ शाला के नाम पर लंबे समय से अवैध रूप से फण्ड वसूला जा रहा था। इसका खुलासा हाल ही में केंद्रीय एनिमल वेल्फेयर के सदस्य राम कृष्ण रघुवंशी की जांच में हुआ है। बताया जा रहा है कि दो दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे रघुवंशी ने जिले में चलायी जा रहीं गौशालाओं का निरीक्षण किया तब पता चला कि यहां त्योंथर तहसील में 8 गौशालाएं ऐसी हैं जहां डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से केवल सरकारी फंड निकाला जा रहा था। उसके बाद उन्होंने तत्काल सभी 8 गौशालाओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इन सभी गौशालाओं से रिकवरी ना होने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी।

8 गौशालाएं ब्लैक लिस्टेड- रीवा जिले में लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि यहां गौशालाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये शिकायतें केंद्रीय पशु कल्याण समिति तक पहुंच गयी थीं। इसकी जांच के लिए दिल्ली से समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी को रीवा भेजा गया। यहां पर उन्होंने जिले भर में भ्रमण किया। इस दौरान त्योंथर तहसील क्षेत्र में तकरीबन 8 गौशालाएं फर्जी निकलीं। उन सभी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया।

डिस्पेंसरी के नाम पर चंदा वसूली

केंद्रीय पशु कल्याण समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने जब शिकायत के आधार पर गौशालाओं का भ्रमण किया तो देखा कि कई जगह डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से सरकार से फंड वसूले जा रहे हैं। इन गौशालाओं को संचालित करने वाले प्राइवेट एनजीओ को रिकवरी का नोटिस भेज दिया। रिकवरी नहीं मिलने पर उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी।

प्रशासन ने नहीं किया सहयोग

केंद्रीय पशु कल्याण समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने बताया कि जब वह जांच के लिए रीवा पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत उनकी जानकारी प्रशासन को दी गई। परंतु जांच में उन्हें प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला। प्रशासन का कोई भी आदमी 2 दिन तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा। जाहिर है प्रशासन में बैठे लोगों की मिलीभगत से ही ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा होगा। रघुवंशी का मानना है प्रशासन को पहले ही अपनी गलती का आभास हो गया था इस वजह से वह जांच में सहयोग के लिए नहीं पहुंचा।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, लेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)